ISSN: 3107-5088 (ONLINE)
ISSN: 3107-4898 (PRINT)

www.cognitivethinking.in

Cognitive Thinking: An International Journal of Interdisciplinary Studies

(An International, Open Access, Peer-Reviewed , Refereed & ISO Certified Journal)

Vol. 1 & Issue 4 (October - December 2025)

Editor-in-Chief
Dr. Kanwar Pal Singh

Cognitive Thinking: An International Journal of Interdisciplinary Studies
Volume-1, Issue-4 (October-December 2025), pp.51-57, ISSN: 3107-5088
www.cognitivethinking.in

प्रयागराज जिले के ग्रामीण परिवारों में खाद्य असुरक्षा की व्यापकता: एक क्षेत्रीय अध्ययन

1. आशीष कुमार सिंह*
शोधार्थी, जे. एस. पी. जी. कॉलेज, सिकंदराबाद, बुलंदशहर
2. डॉ लोकेश कुमार
अर्थशास्त्र विभाग, जे.एस.पीजी कॉलेज, सिकन्दराबाद , बुलन्दशहर

Article: Received: 10/12/2025, Accepted: 19/12/2025, Published:30/12/2025
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18093170.

© 2025 The Author(s). This is an Open Access article/ Journal distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are properly credited (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

सारांश: यह अध्ययन प्रयागराज जिले के ग्रामीण परिवारों में खाद्य असुरक्षा की व्यापकता, उसके निर्धारकों तथा प्रभावों का क्षेत्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन के लिए प्रयागराज के 500 ग्रामीण परिवारों का प्राथमिक डेटा एकत्रित किया गया, जिसमें परिवार की आय, भूमि स्वामित्व, महिला शिक्षा, और सरकारी लाभ सहित विविध सामाजिक-आर्थिक घटक शामिल थे। खाद्य असुरक्षा मापन के लिए परिवारिक खाद्य असुरक्षा पहुँच मापन पैमाना (HFIAS) का उपयोग हुआ और खाद्य असुरक्षा की स्थिति को बाइनरी वर्गों में वर्गीकृत किया गया। सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल का प्रयोग किया गया, जिसने आय, भूमि का आकार, महिला शिक्षा, और सरकारी लाभ को खाद्य असुरक्षा के महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में पहचाना। आय में वृद्धि से खाद्य असुरक्षा की संभावना में कमी पाई गई, और भूमि स्वामित्व तथा महिला शिक्षा के प्रभाव सबसे अधिक शक्तिशाली मिले। सरकारी सहायता योजनाओं के लाभार्थी परिवारों को भी खाद्य सुरक्षा में बहुमूल्य सहायता मिली। अध्ययन के निष्कर्ष स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा सम्बंधित नीतियों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित सामाजिक-आर्थिक हस्तक्षेपों की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। यही नहीं, कोविड-19 महामारी ने ग्रामीण खाद्य असुरक्षा की स्थिति को और जटिल बनाया है, जिसके परिणामस्वरूप सतत् निगरानी व हस्तक्षेप आवश्यक हो गए हैं। यह शोध ग्रामीण खाद्य असुरक्षा की बहुआयामी जटिलताओं को समझने तथा नीति निर्माण के लिए साक्ष्य आधारित सुझाव प्रस्तुत करने में योगदान देता है, जो प्रयागराज जिले सहित समान समसामयिक ग्रामीण इलाकों के लिए उपयोगी होगा।

मुख्य शब्द: ग्रामीण खाद्य असुरक्षा, परिवार आधारित पोषण, महिला शिक्षा और खाद्य सुरक्षा, कृषि भूमि स्वामित्व, आय और पोषण स्तर।

1. प्रस्तावना

खाद्य असुरक्षा का मुद्दा विश्वभर में सामाजिक और आर्थिक विकास के मार्ग में एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है। भारत, विशेषकर इसके ग्रामीण क्षेत्र, जहां अधिकांश आबादी ग्रामीण आजीविका पर निर्भर है, खाद्य असुरक्षा का मामला अत्यंत गंभीर है, अफ़रीदी (2010)। खाद्य असुरक्षा की परिभाषा में न केवल भोजन की अपर्याप्तता को शामिल किया जाता है, बल्कि भोजन की गुणवत्ता, विविधता और बच्चों तथा वयस्कों के पोषण स्तर को भी बैठाया जाता है, जो कि एक स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। उत्तर प्रदेश की स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और यहां ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य असुरक्षा काफी हद तक फैली हुई है, IIPS और ICF (2017)।

प्रयागराज जिला भी इस समस्या से अछूता नहीं है, जहां ग्रामीण परिवारों की आजीविका कृषि पर निर्भर होने के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारकों से प्रभावित है। 2015-16 के ग्रामीण परिवारों के राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार, प्रयागराज में लगभग 30% परिवार खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, जो न केवल पोषण की कमी बल्कि सामाजिक आर्थिक असमानताओं का परिणाम है। इसके अतिरिक्त, कोविड-19 महामारी ने आर्थिक अस्थिरता को बढ़ावा दिया जिससे खाद्य असुरक्षा की स्थिति और अधिक गंभीर हुई है, IIPS और ICF (2017); अलाबी एवं अन्य (2023)।

वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य प्रयागराज जिले के ग्रामीण इलाके में खाद्य असुरक्षा की व्यापकता की जांच करना है, और इसके तहत सामाजिक-आर्थिक, पर्यावरणीय और जनसांख्यिकीय कारकों का आकलन करना है जो खासकर भोजन की उपलब्धता, पहुंच, और पोषण स्थिति को प्रभावित करते हैं। कई अन्य अध्ययनों ने भी यह पुष्टि की है कि आय स्तर, भूमि स्वामित्व और सामाजिक सशक्तिकरण खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महिलाएं और बच्चे खाद्य असुरक्षा के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं, इसलिए महिलाओं की शिक्षा और स्थिति का इस संदर्भ में अध्ययन आवश्यक है। प्रयागराज जिले में मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर खाद्य असुरक्षा का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ विकास को प्रभावित करता है, जो एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय है FAO(2015); IIPS एवं ICF (2017)।

खाद्य असुरक्षा का प्रभाव केवल पोषण तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आजीविका के अवसरों पर भी विपरीत प्रभाव डालती है, जिससे गरीबी और सामाजिक असमानता का चक्र बनता है। इस संदर्भ में सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और अन्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं का महत्व बढ़ जाता है, लेकिन इन योजनाओं की प्रभावशीलता क्षेत्र विशेष में भिन्न होती है। प्रयागराज में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और ग्रामीण परिवारों की खाद्य सुरक्षा के बीच का अंतर इस अध्ययन का एक केंद्र बिंदु होगा बालराजन एवं अन्य (2016)।

इस प्रकार यह क्षेत्रीय अध्ययन खाद्य असुरक्षा के पैमाने, कारणों और प्रभावों को समझने में मदद करेगा और नीति निर्धारण के लिए ठोस साक्ष्य प्रदान करेगा। इसके साथ ही यह ग्रामीण परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुधारने हेतु योजनाएं तैयार करने में सहायक होगा।

2. साहित्य समीक्षा

खाद्य असुरक्षा देश के ग्रामीण क्षेत्रों की एक गंभीर सामाजिक-आर्थिक समस्या है, जिसे कई राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा उच्च प्राथमिकता दी जाती रही है। भारतीय ग्रामीण परिवारों में खाद्य असुरक्षा की व्यापकता और उसकी गंभीरता को समझने के लिए विभिन्न आंकड़ों का उपयोग करते हुए कई सूक्ष्म और राष्ट्रीय स्तर के अध्ययन किए गए हैं। 2015-16 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-4) और अंतर्राष्ट्रीय संस्था IIPS एवं ICF (2017) के अनुसार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ग्रामीण परिवारों में खाद्य असुरक्षा और पोषण स्तर में उल्लेखनीय असमानताएं देखी गई हैं। प्रयागराज जिले के लिए विस्तृत आंकड़े भी विषय के क्षेत्रीय आयाम को समझने में सहायक हैं।

खाद्य असुरक्षा के सामाजिक-आर्थिक निर्धारकों की पहचान में भूमि की उपलब्धता, परिवार की आय, शिक्षा स्तर, और सामाजिक संवेदना प्रमुख भूमिका निभाते हैं। FAO, IFAD, UNICEF, WFP की रिपोर्ट (2017) में इस बात पर जोर दिया गया है कि ग्रामीण खाद्य असुरक्षा का प्रभाव परिवार की आजीविका, बच्चों के पोषण, तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता से जुड़ा होता है। प्रयागराज के ग्रामीण इलाकों में आय के अलावा, महिलाओं की शिक्षा और गृहस्थी में उनकी भागीदारी खाद्य सुरक्षात्मक कारकों के रूप में महत्वपूर्ण हैं।
COVID-19 महामारी ने खाद्य असुरक्षा की समस्या को और अधिक गहरा किया है। अलाबी एवं अन्य (2023) की रिपोर्ट में बताया गया है कि महामारी के दौरान लॉकडाउन और रोजगार के अवसरों की कमी के कारण किसानी और पारंपरिक आजीविका के क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यह प्रभाव स्थानीय सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को और बढ़ाता है, जो प्रयागराज जैसे जिलों में लंबे समय तक खाद्य असुरक्षा का कारण बन सकता है।
सामाजिक नीति के संदर्भ में, भारत सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) ग्रामीण परिवारों को खाद्य असुरक्षा से बचाने के लिए महत्वपूर्ण हैं, परंतु अध्ययन बताते हैं कि वितरण की पारदर्शिता, लाभार्थी की पहचान, और गुणवत्ता नियंत्रण क्षेत्रों में अभी भी कई कमियाँ हैं। इन नीतियों की प्रभावशीलता पर इलाहाबाद (प्रयागराज) जिले के संदर्भ में विशेष अध्ययन आवश्यक है, ताकि स्थानीय जरूरतों और चुनौतियों को समझा जा सके, कुबेर (2024) ।
मूल्य वर्धित दृष्टिकोण में, यह अध्ययन प्रयागराज जिले के ग्रामीण परिवारों की खाद्य असुरक्षा की स्थानीय वास्तविकताओं को सामने लाएगा, जो पूर्व के सभी अध्ययन से भिन्न है क्योंकि यह न केवल राष्ट्रीय और राज्य स्तर के डेटा को जांचता है बल्कि स्थानीय सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों को भी शामिल कर उनके बीच अंतर्संबंधों का विश्लेषण करेगा। इससे क्षेत्रीय नीति निर्माण और लक्षित हस्तक्षेप के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान होंगे। यह दृष्टिकोण प्रयागराज के ग्रामीण खाद्य असुरक्षा को व्यापक सामाजिक आर्थिक, पोषण और स्वास्थ्य संदर्भों में समझने के लिए सबसे प्रासंगिक और नवीनतम व्यावहारिक योगदान के रूप में देखा जा सकता है।

3. शोध प्रश्न एवं परिकल्पना

शोध प्रश्न

प्रयागराज जिले के ग्रामीण परिवारों में खाद्य असुरक्षा की मौजूदा स्थिति और उसके सामाजिक-आर्थिक, जनसांख्यिकीय, और पर्यावरणीय कारणों की पहचान हेतु निम्नलिखित शोध प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं:

- प्रयागराज जिले के ग्रामीण परिवारों में खाद्य असुरक्षा की व्यापकता और गंभीरता कैसी है?
- सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय कारकों (जैसे, आय, भूमि स्वामित्व, परिवार आकार, महिला शिक्षा, रोजगार) का खाद्य असुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है?
- खाद्य असुरक्षा का परिवार के स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका पर क्या प्रभाव है?
- खाद्य असुरक्षा के प्रति ग्रामीण परिवार किस प्रकार की स्थानीय रणनीतियाँ अपनाते हैं?
- किस प्रकार की नीतिगत सिफारिशें प्रयागराज जिले के स्थानीय संदर्भ में खाद्य असुरक्षा को कम करने में उपयोगी हो सकती हैं?

परिकल्पना

- आर्थिक स्थिति की परिकल्पना: जिन परिवारों की मासिक आय कम है, उनमें खाद्य असुरक्षा की व्यापकता अधिक होगी। सागर एवं अन्य (2024)
- भूमि स्वामित्व की परिकल्पना: भूमि धारिता वाले परिवारों में खाद्य असुरक्षा की संभावना कम होगी क्योंकि उनके पास स्वयं का उत्पादन उपलब्ध होगा। IIPS & ICF (2017)

- महिला शिक्षा की परिकल्पना: महिला सशक्तिकरण व शिक्षित महिला वाले परिवारों में खाद्य असुरक्षा की दर अपेक्षाकृत कम होगी। कुबेर (2024)
- सरकारी सहायता की परिकल्पना: जिन परिवारों को सरकारी खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिला है उन्हें खाद्य असुरक्षा की स्थिति में कमी देखने को मिलेगी। बालराजन एवं अन्य (2016)
- स्वास्थ्य प्रभाव की परिकल्पना: परिवार में उच्च खाद्य असुरक्षा बाल स्वास्थ्य व पोषण स्तर पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। IIPS एवं ICF (2017); कुबेर (2024)

4. शोध पद्धति

इस अध्ययन का उद्देश्य प्रयागराज जिले के ग्रामीण परिवारों में खाद्य असुरक्षा की व्यापकता और इसके सामाजिक-आर्थिक निर्धारकों का विश्लेषण करना है। इसके लिए प्राथमिक, द्वितीयक और सरकारी स्रोतों से डेटा एकत्रित किया गया। प्राथमिक डेटा के रूप में प्रयागराज जिले के 500 ग्रामीण परिवारों का सर्वेक्षण किया गया। प्रश्नावली में परिवार की आय, भूमि स्वामित्व, महिला शिक्षा, सरकारी लाभ तथा खाद्य असुरक्षा मापन के लिए HFIAS शामिल थे। द्वितीयक डेटा के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं स्थानीय सरकारी रिपोर्टों का सहारा लिया गया। डाटा संग्रहण वर्ष 2024 के मई से सितंबर तक हुआ। 500 परिवारों का चयन बहु-स्तरीय यादृच्छिक नमूना विधि से किया गया, जो प्रयागराज के विभिन्न ग्रामीण ब्लॉकों को सम्मिलित करता है। सैंपल आकार सांख्यिकीय विश्वसनीयता प्रदान करता है।

आय, भूमि आकार, महिला शिक्षा व सरकारी लाभ स्वतंत्र चर हैं, जबकि खाद्य असुरक्षा HFIAS स्कोर से मापा गया निर्भर चर है। खाद्य असुरक्षा को बाइनरी (FoodInsecureFlag) में परिवर्तित कर लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल लागू किया गया:

$$FoodInsecureFlag = \beta_0 + \beta_1 Income + \beta_2 LoadSize + \beta_3 FemaleEducation + \beta_4 GovtBenefits + \varepsilon$$

डेटा विश्लेषण के लिए *Stata* और *Python* के *statsmodels* पैकेज का उपयोग किया गया। मॉडल का फिट अच्छा रहा (Pseudo R-squ.: 0.76, $p < 0.001$), जो चर के प्रभाव की पुष्टि करता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन विश्लेषण से दिखा कि आय, भूमि आकार, महिला शिक्षा, और सरकारी लाभ सभी का खाद्य असुरक्षा पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव है, अर्थात् इन कारकों की वृद्धि से खाद्य असुरक्षा घटती है। आय का कोएफिसिएंट -0.0013 (p=0.000), भूमि का -2.9931 (p=0.000), महिला शिक्षा का -3.5439 (p=0.000), और सरकारी लाभ का -2.2330 (p=0.000) था, जो सांख्यिकीय रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

β_0 (Intercept) वह मूलांक है, जो तब दर्शाता है जब सभी स्वतंत्र चरों (आय, भूमि का आकार, महिला शिक्षा, सरकारी लाभ) का मान 0 हो। β_1, β_2, β_3, β_4 स्वतंत्र चरों के लिए रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं। ये कोएफिशिएंट्स यह बताते हैं कि किसी एक स्वतंत्र चर में इकाई परिवर्तन से खाद्य असुरक्षा की लॉजिट संभावना में कितना फर्क पड़ेगा। उदाहरण के लिए, $в_1$ आय का कोएफिशिएंट है, जो यह दर्शाता है कि आय में बढ़ोतरी खाद्य असुरक्षा की संभावना को कैसे प्रभावित करती है। p या p-value प्रत्येक कोएफिशिएंट के महत्व को दर्शाता है। यह सांख्यिकीय परीक्षण की संभावना है कि परिणाम संयोग से मिले हैं। यदि p-value कम (आमतौर पर < 0.05) हो, तो हम यह मान सकते हैं कि संबंधित चर का खाद्य असुरक्षा पर प्रभाव महत्वपूर्ण है, होसमेर एवं अन्य (2013); मेनेर्ड (2002)।

चित्र 1 लॉजिस्टिक रिग्रेशन के फलस्वरूप उत्पन्न कोएफिशिएंट्स का बार चार्ट है, जिसमें प्रयागराज के ग्रामीण परिवारों में खाद्य असुरक्षा के निर्धारकों पर विभिन्न कारकों के प्रभाव को दिखाया गया है। यह ग्राफ प्रयागराज के ग्रामीण परिवारों में खाद्य असुरक्षा के निर्धारकों के प्रभाव को दर्शाता है। X-अक्ष पर स्वतंत्र चर हैं आय, भूमि

का आकार, महिला शिक्षा, और सरकारी लाभ । Y-अक्ष पर इनके कोएफिशिएंट की मान है। इस प्रकार, ये कोएफिशिएंट्स इस बात की पुष्टि करते हैं कि आय, भूमि स्वामित्व, महिला शिक्षा और सरकारी सहायता खाद्य असुरक्षा के जोखिम को कम करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। ये परिणाम नीति निर्धारकों के लिए मूल्यवान संकेत हैं कि खाद्य असुरक्षा को कम करने के लिए आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक हस्तक्षेप आवश्यक हैं। ग्राफ में एक क्षैतिज रेखा (y=0) भी है, जो सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के बीच विभाजक है। सभी बार नकारात्मक पक्ष में हैं, जो सकारात्मक प्रभाव (खाद्य सुरक्षा) को दर्शाते हैं।

चित्र 1: लॉजिस्टिक रिग्रेशन के फलस्वरूप उत्पन्न कोएफिशिएंट्स का बार चार्ट

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी खाद्य असुरक्षा के निर्धारकों के संदर्भ में इसी तरह के निष्कर्ष पाए गए हैं, जैसे कि आय और शिक्षा का खाद्य सुरक्षा में सुधार लाना । इसलिए, यह स्थानीय रूप से प्रयागराज की ग्रामीण आबादी के लिए भी सटीक और प्रासंगिक समझ प्रदान करता है।

5. परिणाम और चर्चा

इस अध्ययन में प्रयागराज जिले के 500 ग्रामीण परिवारों से एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण किया गया। खाद्य असुरक्षा की व्यापकता को मापने के लिए HFIAS स्कोर का उपयोग किया गया, जहां 20 से अधिक स्कोर वाले परिवार खाद्य असुरक्षित माने गए। इस आधार पर, कुल नमूने में लगभग 42% परिवार खाद्य असुरक्षा के दायरे में पाए गए।

लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आय का कोएफिशिएंट -0.0013 ($p<0.001$) पाया गया, जो यह स्पष्ट करता है कि आय में वृद्धि से खाद्य असुरक्षा की संभावना घटती है। उदाहरण के लिए, एक परिवार की मासिक आय में 1000 रुपये की वृद्धि खाद्य असुरक्षा की संभावना को लगभग 27% तक कम कर सकती है। यह ग्रामीण इलाकों में आय आधारित खाद्य असुरक्षा को दर्शाता है जहाँ आय वृद्धि नगण्य होने पर परिवार खाद्य संकट में फंस सकते हैं।

भूमि के आकार का कोएफिशिएंट -2.9931 ($p<0.001$) है, जो भूमि स्वामित्व को खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण कारक बनाता है। भूमि वाले परिवारों में अपनी खेती के कारण खाद्य दायित्व कम होता है जबकि भूमिहीन परिवारों को खाद्यान्न खरीदने पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए भूमि स्वामित्व ग्रामीण खाद्य सुरक्षा में प्रमुख भूमिका निभाता है।

महिला शिक्षा का प्रभाव भी काफी महत्वपूर्ण (-3.5439, $p<0.001$) पाया गया। यह बताता है कि जहां महिलाएं शिक्षित होती हैं, वहां परिवार की खाद्य सुरक्षा बेहतर होती है। महिला सशक्तिकरण से घरेलू पोषण और आय में सुधार होता है, जो खाद्य असुरक्षा को कम करने में सहायक होता है।

सरकारी लाभ का कोएफिशिएंट भी नकारात्मक (-2.2330, $p<0.001$) है, जिसका अर्थ है कि सरकारी योजनाओं से लाभ पाने वाले परिवारों में खाद्य असुरक्षा की संभावना कम है। हालांकि, कार्यक्रमों की पहुंच और प्रभावशीलता में क्षेत्रीय भिन्नताएं अभी भी एक चुनौती हैं।

मॉडल का pseudo-R-squared 0.76 के लगभग है, जो बताता है कि ये चार स्वतंत्र चर (आय, भूमि, महिला शिक्षा, सरकारी लाभ) परिवारों की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सभी कारक सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण पाए गए ($p<0.001$), जो न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से खाद्य सुरक्षा का प्रमाण है।

6. नीति-निहितार्थ

प्रयागराज जिले के ग्रामीण परिवारों में खाद्य असुरक्षा के अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर निम्नलिखित नीति-निहितार्थ सुझाए जा सकते हैं:

खाद्य असुरक्षा कम करने के लिए प्राथमिकता आर्थिक सशक्तिकरण की होनी चाहिए। ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने हेतु कृषि, स्वरोजगार, और गैर-कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। भूमि स्वामित्व को बढ़ावा देने से स्थानीय उत्पादक क्षमता बढ़ेगी और खाद्य सुरक्षा बेहतर होगी। महिला शिक्षा एवं सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह घरेलू पोषण और खाद्य उपलब्धता में सुधार लाता है।

सरकारी खाद्य सुरक्षा योजनाओं जैसे पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम (PDS) और अन्य लाभों की पहुंच और प्रभावशीलता सुनिश्चित करनी होगी। वितरण तंत्र को पारदर्शी और जमीनी स्तर तक पहुंचता बनाना आवश्यक है, जिससे उचित लाभार्थियों तक सहायता पहुंचे। इसके साथ ही, स्थानीय स्तर पर पोषण संवेदनशील कृषि और खाद्य विविधता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।

यह नीतिगत सुधार प्रयागराज जिले के ग्रामीण क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा स्थिति में वास्तविक और स्थायी सुधार ला सकते हैं, जिससे समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को बल मिलेगा ।

7. निष्कर्ष

यह शोध प्रयागराज जिले के ग्रामीण परिवारों में खाद्य असुरक्षा की स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। शोध में प्रयुक्त प्रश्नावली, सांख्यिकीय मॉडलिंग (लॉजिस्टिक रिग्रेशन) और प्राथमिक डेटा संग्रह से प्राप्त मुख्य निष्कर्ष बताते हैं कि आय, भूमि का आकार, महिला शिक्षा, एवं सरकारी लाभ परिवारों की खाद्य सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। आय वृद्धि, बेहतर भूमि स्वामित्व, एवं महिला शिक्षा से खाद्य असुरक्षा में कमी देखी गई। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी खाद्य सहायता प्राप्त हुई, पर वितरण तंत्र में सुधार की आवश्यकता बनी हुई है। कोविड-19 महामारी ने खाद्य असुरक्षा की स्थिति को और जटिल बना दिया है, जिससे सतत निगरानी एवं नीति हस्तक्षेप अनिवार्य हैं। भविष्य के शोध में अधिक व्यापक और विविध ग्रामीण क्षेत्रीय डेटा का संग्रह आवश्यक होगा। गुणात्मक विश्लेषण के साथ-साथ कोविड-19 जैसी वैश्विक आपदाओं के खाद्य असुरक्षा पर प्रभाव की गहराई से जांच होनी चाहिए। साथ ही, सरकारी योजनाओं व वितरण तंत्र की प्रभावशीलता का निरंतर मूल्यांकन और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप नीतिगत सुधारों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के प्रभावों की अतिरिक्त पड़ताल की भी सिफारिश की जाती है।

8. सन्दर्भ सूची

[1] अफ़रीदी, एफ. (2010)। बाल कल्याण कार्यक्रम और बाल पोषण: भारत में अनिवार्य स्कूल भोजन कार्यक्रम से साक्ष्य। विकास अर्थशास्त्र, 92(2), 152–165।
[2] IIPS और ICF (2017)। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-4) भारत, 2015-16। दिल्ली: अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान और आईसीएफ इंटरनेशनल।
[3] अलाबी, एम.ओ., एवं अंग्वेनयमा, ओ. (2023)। "कोविड-19 के दौरान वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन और खाद्य सुरक्षा: पोस्ट कोविड-19 युग के लिए स्मार्ट खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण"। ब्रिटिश फूड जर्नल, वॉल्यूम 125, अंक 1, पृष्ठ 167–185।
[4] खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO)। (2015)। वैश्विक खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट 2015। रोम: संयुक्त राष्ट्र संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन।
[5] बालराजन, यार्लिनी एवं रीच, माइकल आर. (2016)। बाल पोषण नीति की राजनीतिक अर्थव्यवस्था: भारत के समेकित बाल विकास सेवाओं (ICDS) योजना का गुणात्मक अध्ययन। खाद्य नीति, 62, 88–98।
[6] कुबेर सिंह गुरुपंच. (2024)। भारत में संपोषित पर्यटन विकास एवं पर्यावरण. अंतरराष्ट्रीय पत्रिका समीक्षा और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान, 12(2):104-106।
[7] सागर सिंह, कुमार प्रणव वर्मा. (2024) । प्रयागराज जनपद (उ.प्र.) में भूमि उपयोग प्रतिरूप का अध्ययन। अंतरराष्ट्रीय पत्रिका समीक्षा और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान, 12(2):131-6।
[8] होसमेर, डी.डब्ल्यू., लेमेशो, एस., एवं स्टर्डिवेंट, आर.एक्स. (2013)। एप्लाइड लॉजिस्टिक रिग्रेशन (तीसरा संस्करण)। वाइली।
[9] मेनेर्ड, एस. (2002)। एप्लाइड लॉजिस्टिक रिग्रेशन विश्लेषण। सेज।